भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 673

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए शहर विकसित करने की योजना

673. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आठ हजार करोड़ रुपये खर्च करके आठ नए शहर विकसित करने की सरकार की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नए शहरों के स्थानों के बारे में औपचारिक घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है और उनके विकास की समय-सूची क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में आठ नए शहर विकसित किए जाएंगे और क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में भी एक नया शहर विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग में नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए निष्पादन आधारित चुनौती निधि के रूप में 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित नए शहर के लिए उपलब्ध राशि 1,000 करोड़ रुपये है। इस निधि के माध्यम से एक राज्य में केवल एक ही नया शहर हो सकता है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, मंत्रालय ने नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए बोली मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया। समिति ने न्यूनतम पात्रता शर्तों और बोली मापदंडों को अंतिम रूप दिया और सभी राज्यों को प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) परिचालित किया गया। मंत्रालय को अंतिम तिथि तक 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूर्वोत्तर राज्यों से गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव न मिलने के कारण, इन राज्यों से नए/संशोधित प्रस्ताव मांगे गए। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्ताव सहित 23 राज्यों से कुल 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव जांच/संवीक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास हैं।

****